तिब्बत में आत्मदाह चीनी आतंक का परिणाम

अभी नवंबर 2012 में चीन के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को चेताया है कि वह तिब्बत के मामले उठाकर चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मत करे। चीन का यह दृष्टिकोण निश्चय ही मानवाधिकार तथा लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। ऐसी चेतावनी जारी करके चीन की सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की अवहेलना की है।

इसी नंवबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रमुख नवी पिल्लै ने तिब्बत में चीन द्वारा जारी मानवाधिकार हनन के मामलों को ठोस प्रमाणों के साथ गंभीरतापूर्वक उठाया था। मानवाधिकार परिषद का स्पष्ट मत है कि तिब्बतियों को आत्मदाह करने के लिए चीनी प्रशासन बाध्य कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह का सिलसिला थम नहीं रहा है क्योंकि चीन की सरकार अहिंसक एवं शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को भी हिंसक उपायों से कुचलने में लगी है। तिब्बत के अंदर और तिब्बत के बाहर भी अनेक तिब्बती यह सोचकर स्वयं को आग के हवाले कर रहे हैं कि इससे विश्व समुदाय का घ्यान तिब्बत की दुर्दशा की ओर जरूर जाएगा।

चीनी क्रूरता के खिलाफ कई तिब्बतियों द्वारा अपने शरीर में खुद आग लगा लेना और जलते हुए तड़प–तड़प कर मर जाना एक अत्यंत ही विचलित कर देने वाला कठोर कदम है। तिब्बत की आजादी के लिए प्रेरणापूर्ण शहादत और आत्मबलिदान ही प्रशंसनीय है। भारतीय आजादी की लड़ाई में भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। लेकिन आत्मदाह का तरीका छोड़ना होगा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे, परमपावन दलाई लामा तथा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रमुख नवी पिल्लै ने भी तिब्बती आंदोलनकारियों से अपील की है कि वे आत्मदाह नहीं करें।

आश्चर्यजनक रूप से चीन की सरकार तिब्बत में जारी आत्मदाह की घटनाओं के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा को तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका कहना है कि ये ही तिब्बत के लोगों को चीन के खिलाफ उकसा रहे हैं तथा उन्हें आत्मदाह के लिए प्रेरित–प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपनी इसी अमानवीय सोच के कारण चीन की सरकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तिब्बत संबंधी रिपोर्ट एवं सुझावों की तीखी आलोचना कर रही है। तिब्बत में चीन कई तरह से मानवाधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। वहां चीन के लोग सुनियोजित तरीके से बसाये जा रहे हैं जिससे तिब्बत में तिब्बती ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। झूठे आरोपों के आधार पर तिब्बतियों को जेलों में डाला जाता है। उनमें कइयों को गायब कर दिया जाता है। अनेक तिब्बतियों को तरह–तरह से प्रताड़ित–पीड़ित किया जाता है। भिक्षु–भिक्षुणियों, बच्चों तथा बूढ़ों को भी चीनी प्रशासन अपनी क्रूरता का शिकार बना रहा है। ये सारे तथ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए दिन उजागर हो रहे हैं। इससे साम्राज्यवादी चीन की बौखलाहट एवं बेचैनी बढ़ती जा रही है।

चीन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाह है कि तिब्बत में वास्तविक स्थिति को समझने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय जांच दल आने दिया जाए। ऐसे सुझाव पहले भी विभिन्न संस्थाओं ने चीन सरकार को दिए हैं लेकिन बेनकाब होने के भय से चीन की सरकार ने उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया है। दलाई लामा जी की हाल की अमरीका एवं जापान यात्रा तथा तिब्बती प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे की अमेरिका यात्रा की चीन ने कटु आलोचना की है। हर बार की तरह इस बार भी। उसे लगता है कि इन यात्राओं से तिब्बत की आजादी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ता जा रहा है। तिब्बत समर्थक अंतर्राष्ट्रीय समूहों के सम्मेलन ने भी चीन की नींद हराम कर दी है।

चीन में नेतृत्व परिवर्तन से भी चीन की तिब्बत नीति में बदलाव नहीं आने वाला। चीन का पूरा तंत्र ही साम्राज्यवादी है। ऐसे में जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तिब्बत के संदर्भ में विशेष अधिवेशन बुलाए। चीन द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर रोक लगानी ही होगी। तिब्बत स्वतंत्र देश था, जिस पर चीन ने बलपूर्वक अवैध कब्जा कर रखा है। तिब्बत का प्रश्न चीन का आंतरिक मामला कभी नहीं हो सकता। तिब्बत की आजादी तिब्बतियों का अधिकार है। तिब्बत समर्थक समूहों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जरिये यह संकल्प धर्मशाला में जोरदार तरीके से उभरा है। इसी समय चीन की साम्यवादी पार्टी नेता और नीति में बदलाव लाने के नाम पर फिर से अपनी विस्तारवादी मंसूबों को मजबूत करने में लगी है।

इस समय भारत सरकार को चाहिये कि वह चीन के नए नेतृत्व के साथ तिब्बत के समर्थन में खुलकर बात करे। वह बताए कि तिब्बत पहले भारत एवं चीन के बीच एक मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) था। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत को इस कार्य में अमरीका के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा का रचनात्मक सहयोग मिलना भी संभव है क्योंकि चीनी चंगुल से तिब्बत की आजादी सम्पूर्ण मानवता के हित में होगी। इससे विस्तारवादी चीन का भी कल्याण होगा।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

मो.–9829806065, 8764060406

E-mail & facebook: shyamnathji@gmail.com

तिब्बत समर्थक संगठनों ने तिब्बत के बारे में अपनी प्रतिबद्धता फिर दोहराई, ज्यादा प्रयास का प्रण किया

(फायूल, 19 नवंबर, 2012)

यहां रविवार को खत्म हुए अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक संगठनों के तीन दिवसीय बैठक में तिब्बत में बढ़ते संकट पर कार्रवाई की मांग की गई और "तिब्बत मसले के राजनीतिक समाधान के लिए एकसाथ मिलकर काम करने की नए सिरे से प्रतिबद्धता जाहिर की गई।"

बैठक में अंतिम दिन एक कार्ययोजना स्वीकार की गई जिसका लक्ष्य तिब्बत के भीतर आत्मदाह की मौजूदा लहर के संदर्भ में तिब्बती प्रतिरोध बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर, खासकर एशिया में तिब्बत के लिए ज्यादा राजनीतिक समर्थन जुटाना है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में जारी समापन बयान में बैठक में आए प्रतिनिधियों ने उन तिब्बतियों की भावना के प्रति "गहरी पीड़ा" व्यक्त की जो "राजनीतिक प्रतिरोध की कार्रवाई के तहत आत्मदाह करने को मजबूर हुए हैं।" संगठनों के बयान में कहा गया है, "आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को उनके मातृभूमि में वापस लाने की तिब्बतियों की आकांक्षा के साथ हम दृढ़ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इस संकट के लिए पूरी तरह से चीन के नेता और पिछले 60 वर्ष से जारी उनकी विफल नीतियां जिम्मेदार रही हैं। हम चीन के नए नेताओं से आह्वान करते हैं कि वे तत्काल आत्मदाह की मूल वजहों का समाधान करें।"

तिब्बत में अग्निमय विरोध प्रदर्शनों में चेतावनीजनक वृद्धि हो रही है और इस महीने ही वहां तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की 14 घटनाएं हुई हैं। चीन के कब्जे के विरोध में तिब्बत में वर्ष 2009 में कुल 76 तिब्बतियों ने खुद को आग लगा लिया है। इस बैठक में आए 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने खासकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव शी जिनपिंग और नई पोलित ब्यूरो स्थायी समिति से आह्वान किया कि वह "तिब्बती जनता के सभी वैधानिक शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए और इस बात को समझे कि शांतिपूर्ण समाधान तिब्बती और चीनी जनता दोनों के लिए हितकारी है।"

शनिवार को प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए परमपावन दलाई लामा ने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बत की स्थिति गंभीर है और चीन सरकार एवं तिब्बतियों को "परस्पर समझ और सम्मान के आधार पर कोई हल निकालने की जरूरत है।"

कुल 43 देशों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी–अपनी सरकारों से भी यह मांग की कि वे "तत्काल और समन्वित कार्रवाई शुरू करें, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंचों पर कार्रवाई भी शामिल हो, ताकि चीन पर अपनी तिब्बत नीतियों में बदलाव के लिए दबाव बने।" इसके लिए एशियाई तिब्बत समर्थक संगठनों का एक गठबंधन भी बनाया गया है।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने इस माह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से यह अनुरोध किया था कि वह तिब्बत पर एक विशेष सत्र का आयोजन करे। उनकी मांग के मुताबिक तिब्बत पर एक संपर्क समूह का गठन भी कर लिया गया है।

बैठक के समापन सत्र में पूर्व चीनी राजनीतिक कैदी और 1989 के टिनामेन नरसंहार से बच गए यिआंग जियानली ने कहा कि चीनी जनता को तिब्बत पर अपनी चुप्पी तोड़नी ही होगी। लोकतंत्र समर्थक इस आंदोलनकारी ने कहा, "हमें उन तक पहुंचने और उन्हें सच बताने, यह निवेदन करने कि वे अपने विवेक से काम लें और उन्हें यह आभास कराने के लिए विशेष प्रयास करना होगा कि चीनी जनता तिब्बती जनता को उत्पीड़ित कर रही है।"

अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूहों की दूसरी विशेष बैठक भारत के कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज द्वारा आहूत की गई थी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने इसमें सहयोग किया।

तिब्बत के मसले पर अब चीन से दृढ़ता से पेश आ रहा भारतः दलाई लामा

(हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 3 नवंबर)

14वें दलाई लामा ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब चीन से तिब्बत मसले पर बात करते समय 'जरूरत से ज्यादा सचेत" नहीं रहता है और उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि मनमोहन सिंह सरकार चीन से द्विपक्षीय संपर्क में पिछली सरकारों के मुकाबले 'ज्यादा दृढ' है। टोक्यो के रास्ते में एचटी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहाः "पहले मैं कहा करता था कि भारत सरकार तिब्बत पर चीन से बात करने के मामले में जरूरत से ज्यादा सचेत रहती है। लेकिन अब मैंने अपनी धारणा बदल ली है और मैंने यह देखा है कि भारत इस तरह की बातचीत में ज्यादा दृढ़ता से पेश आ रहा है। मैंने यह बदलाव तब देखा जब मुझे नवंबर 2009 में चीन की आपत्ति के बावजूद भारत सरकार ने तवांग जाने की इजाजत दी। इसका एक और उदाहरण यह है कि पिछले साल सितंबर में भारत दौरे पर आए चीनी रक्षा मंत्री लियांग गुआंगली ने दावा किया कि पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पीएलए के कोई सैनिक नहीं हैं, लेकिन अगले ही दिन भारतीय सेना प्रमुख ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पाक अधिकृत क्षेत्र में करीब 4,000 चीनी सुरक्षा कर्मी हैं।"

उनके मुताबिक, भारत और चीन के बीच भरोसा बहाली तब ही हो सकती है, जब तिब्बत में स्थिति फिर से "पूरी तरह से सामान्य" हो जाए। उन्होंने कहा, "दोनों देशों के बीच यदि भय और अविश्वास का माहौल बना रहा तो सीमा विवाद का निपटारा नहीं किया जा सकता।" इस महीने 18वीं राष्ट्रीय जन कांग्रेस के आयोजन के बाद चीनी नेतृत्व में बदलाव के बारे में बात करते हुए दलाई लामा ने कहा वह तिब्बत के बारे में चीन के बदले रवैए के बारे में कुछ कहने से पहले हू जिनताओ से शी जिनपिंग के बीच सत्ता हस्तांतरण तक "देखने और इंतजार करने" की नीति पर चलना पसंद करेंगे।

उन्होंने कहा, "यह कहना कठिन है कि क्या चीन जिनपिंग के नेतृत्व में उदार रवैया अपनाएगा। शी को चीन का नेतृत्व संभालने दें, मैं तिब्बत पर उनकी नीतियों को देखने के बाद ही कोई राय कायम कर सकता हूं।"

जापानी संसद ने तिब्बत मसले पर पूरा समर्थन देने का वायदा किया

(तिब्बत डॉट नेट, टोक्यो, 14 नवंबर)

पार्टी के दायरे से ऊपर उठकर जापान के 150 से ज्यादा सांसदों ने तिब्बत के मसले को अपने पूरे समर्थन का वचन दिया है और चीन सरकार से आग्रह किया है कि वह तिब्बती जनता के गैरकानूनी दमन पर रोक लगाए। जापानी संसद भवन में मौजूद परमपावन दलाई लामा के समक्ष सांसदों का यह संयुक्त बयान पढ़ा गया।

इस बयान में कहा गया है, "चीन सरकार काफी निर्मम तरीके से तिब्बतियों के मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। वह तिब्बतियों की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आज़ादी और आर्थिक गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध लगा रही है और जो लोग विरोध करते हैं उनकी शारीरिक रूप से प्रताड़ना और अन्य तरह के अत्याचार किए जाते हैं। इस तरह के दमन का विरोध करते हुए बहुत से तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। हालांकि, चीन सरकार तिब्बती जनता के शिकायतों का समाधान नहीं कर रही और वह तिब्बत मसले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता शुरू करने के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा बार–बार किए जाने वाले अनुरोध को भी खारिज कर रही है। हम चीन सरकार से यह प्रबल अनुरोध करते हैं कि वह तिब्बती जनता के मानवाधिकारों के गैरकानूनी रूप से दमन पर तत्काल रोक लगाए और स्थिति में सुधार लाए। हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी बिना किसी हिचक के ऐसा ही संदेश देना चाहते हैं।"

परमपावन दलाई लामा "मानव मूल्य और सार्वभौमिक जवाबदेही" विषय पर जापान की विभिन्न पार्टियों के सांसदों के समक्ष व्याख्यान देने संसद में गए थे। दोपहर में परमपावन दलाई लामा ने 'उपचार की बुद्धिमत्ताः शरीर और दिमाग का संतुलन बनाना' विषय पर आयोजित एक समूह चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा में उनके साथ 1987 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले प्रमुख जापानी वैज्ञानिक डॉ. सुजुमी तोनेगावा और टोक्यो विश्वविद्यालय के डॉ. मारोकी गाकिया भी थे। जापान के ह्यूमन वैल्यूज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस चर्चा का संचालन डॉ. बैरी कारजुन ने किया। टोक्यो के रॉयल पार्क होटल के सम्मेलन हॉल में आयोजित इस चर्चा में 1500 से ज्यादा लोग पधारे थे।

दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते हुए 13 तिब्बती युवा गिरफ्तार किए गए

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 13 नवंबर)

तिब्बत को चीनी शासन से पूरी तरह से आज़ाद करने की मांग करने वाले तिब्बती युवा कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं को नई दिल्ली में 12 नवंबर को चीनी दूतावास में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें टीवाईसी के अध्यक्ष श्री सेवांग रिगजिन थे। यह विरोध प्रदर्शन तिब्बत के भीतर रहने वाली तिब्बती जनता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किया गया था। तिब्बत में लगातार आत्मदाह का सिलसिला जारी है और क्विंघई प्रांत के रेबकोंग काउंटी में हजारों तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं।

आंदोलनकारियों ने चीनी दूतावास के बाहर नारे लगाते हुए तिब्बत की आज़ादी का आह्वान किया। पुलिस इन सभी 13 आंदोलनकारियों को पास के चाणक्यपुरी थाने में ले गई। इनमें छह छात्र और दो छात्राएं शामिल थीं।

इस अवसर पर जारी एक बयान में टीवाईसी ने चीन पर यह आरोप लगाया कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे तिब्बतियों की समस्याओं को समाधान करने की बजाय उनका कठोरता से दमन कर रही है। टीवाईसी ने कहा कि चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 71 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं।

नए नेता के साथ अब चीन को भी बदलना होगाः दलाई लामा

(क्योको हासेगावा, एएफपी, योकोहोमा, जापान, 5 नवंबर)

दलाई लामा ने सोमवार, 5 नवंबर को कहा कि चीन के आगामी नेता के शासन के तहत वहां असंतोष की आवाजों को शांत

करने के लिए "गोपनीयता, सेंसरशिप और डराना–धमकाना" निश्चित रूप से बंद होना चाहिए। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने टोक्यो के निकट योकोहोमा में पत्रकारों से कहा कि चीन के आगामी राष्ट्रपति (प्रेसिडेंट इन वेटिंग) शी जिनपिंग के पास अगले वर्षों में राजनीतिक बदलावों को स्वीकार करने के अलावा "और कोई विकल्प नहीं होगा"।

जापान में अपने 12 दिवसीय दौरे के तीसरे दिन दलाई लामा ने कहा, "अब हू जिनताओ युग गुजर चुका है। अब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वहां कुछ राजनीतिक बदलाव के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। हू जिनताओ ने सौहार्दपूर्ण समाज, स्थिर समाज के निर्माण का काम शुरू किया था. इसलिए स्थिर समाज के लिए मुझे लगता है कि धनी और गरीब लोगों में अंतर कम होना चाहिए। साथ ही आपको एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, आज़ाद प्रेस, कानून का शासन भी अपनाना होगा। ये सब बहुत–बहुत महत्वपूर्ण हैं।"

दलाई लामा ने कहा, "इसलिए सौहार्द, स्थिरता हासिल करने का लक्ष्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गोपनीयता, सेंसरशिप और डराने–धमकाने का मतलब है कि उनकी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वास्तविक सौहार्द लाने के लिए आपको खुलापन लाने की जरूरत है।"

चीन दलाई लामा की निंदा करते हुए उन्हें ऐसा 'अलगाववादी' बताता है जो आज़ाद तिब्बत के लिए काम कर रहे हैं, जबकि दलाई लामा बार–बार इसका खंडन करते रहे हैं। गुरुवार को बीजिंग में बंद दरवाजे में शुरु हुई कांग्रेस में चीन के सत्ता के धुरंधर अगले दस साल के लिए एक नए मुखिया का अभिषेक करेंगे। रिश्वतखोरी पर लोगों के बढ़ते गुस्से और असंतुष्टों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुखर विरोध से निपटना उनके कार्यकाल की मुख्य चुनौतिया होंगी। उप राष्ट्रपति शी के इस हफ्ते तरक्की देकर कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना दिए जाने की पूरी उम्मीद है और अगले साल वह दस साल में एक बार होने वाले सत्ता परिवर्तन के तहत हू की जगह देश के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे।

दलाई लामा के जापान में बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और वह इस देश में अक्सर आते रहते हैं। जापान की 12.7 करोड़ जनसंख्या के बहुत से लोग बौद्ध धर्म के कई तत्वों का पालन करते हैं।

77 वर्ष के नोबेल पुरस्कार सम्मानित दलाई लामा ने कहा कि उनका मानना है कि चीन सबसे अच्छी व्यवस्था लोकतंत्र को अपनाकर ही जापान के साथ सीमा विवाद जैसी अपनी समस्याओं से निपट सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद पर बहुत ज्यादा जोर देना ही सभी कठिनाइयों की जड़ है। वहां जो शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जाती हैं "वे अतिरेक वाले हैं जिनमें कहा जाता है कि चीनी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, चीन सबसे अच्छा देश है, यह बहुत ज्यादा भावना आधारित है और यथार्थवादी नहीं है।"

दलाई लामा ने कहा कि "सूचनाओं की कमी" की वजह से बहुत से चीनी लोग जापानी जनता को सिर्फ युद्ध के अत्याचारों के रूप में याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ही जब सितंबर महीने में विवादित पूर्वी चीन सागर द्वीप श्रृंखला का जापान ने राष्ट्रीयकरण किया तब पूरे चीन में जापान विरोध चरम पर पहुंच गया और दुकानें लूटी गई तथा कारोबारी प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई। जब उनसे पूछा गया कि चीन और जापान के बीच विवाद कैसे खत्म हो सकता है तो उन्होंने कहा कि "बुनियादी रूप से मुझे लगता है कि चीन को जापान की जरूरत है और जापान को चीन की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आपको ज्यादा समग्र दृष्टि से सोचना चाहिए। छोटे असंतोष की वजह से टकराव नहीं होना चाहिए। आपको ज्यादा व्यापक तरीके से सोचना चाहिए।"

बाल दिवस पर विद्यार्थियों ने तिब्बत में आत्मदाह करने वालों के लिए मोमबत्तियां जलाईं

(फायूल, 15 नवंबर, 2012)

तिब्बती स्कूलों के छात्रों ने 14 नवंबर को भारत में मनाए जाने वाले बाल दिवस के अवसर पर आमतौर पर होने वाले धूमधाम और उत्सव के विपरीत तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक मोमबत्ती जुलूस का आयोजन किया।

गोपालपुर के तिब्बती चिल्ड्रेंस स्कूल के बच्चों ने स्वयं के प्रयास से ही तिब्बत में आत्मदाह करने वाले वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए प्रार्थनाएं की तथा 10,000 मोमबत्तियां और मक्खन के दिए जलाए गए। स्कूल की विद्यार्थियों की परिषद ने एक बयान में बताया, "हमने तिब्बत के अपने उन भाइयों एवं बहनों के प्रति अपनी समानुभूति और एकजुटता दिखाने के लिए अभियान चलाया जो चीन जनवादी गणतंत्र की कठोर नीतियों के तहत दुःखद राजनीतिक दशाओं में खुद को आग लगाने को मजबूर हो रहे हैं।" बयान में कहा गया है कि, "आज तिब्बत में आत्मदाह करने वालों की संख्या सत्तर को पार कर चुकी है। यह मोमबत्ती जुलूस न सिर्फ चीन की नीतियों का विरोध करने के लिए है बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण निवेदन करने के लिए है कि वह तिब्बत मसले को जल्दी हल करने के लिए गंभीरता से और समय से कार्रवाई करे।" इस मोमबत्ती जुलूस में सैकड़ों विद्यार्थियों और स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

गौरतलब है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता

है। उन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। स्कूल के प्रधानाचार्य फुंसोक टाशी ने बताया कि वैसे तो प्रशासन ने बाल दिवस को पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन पिछले वर्षों के विपरीत इस साल धूमधाम नहीं किया गया।

टाशी ने फायूल को बताया, "मोमबत्ती जुलूस की शुरुआत विद्यार्थियों के परिषद की प्रेरणा से हुई और स्कूल के कर्मचारियों ने इसके लिए चंदा देकर विद्यार्थियों का सहयोग किया।"

तिब्बत में गहराते संकट की वजह से वहां बड़े पैमाने पर चीन विरोधी प्रदर्शन होने लगे हैं और आत्मदाह का सिलसिला शुरू हो गया है जिसकी वजह से 2009 के बाद अब तक 74 तिब्बती खुद को आग के हवाले कर चुके हैं। आत्मदाह करने वाले सभी तिब्बतियों ने तिब्बत को आज़ाद करने और परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने के नारे लगाए थे। सिर्फ नवंबर माह में ही आत्मदाह की ऐसी 12 घटनाएं हो चुकी हैं और हजारों लोगों ने अन्य विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है जिनमें पूर्वी तिब्बत के रेबकोंग क्षेत्र के स्कूली विद्यार्थी भी शामिल थे।

तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के नए नेताओं का स्वागत किया

(गिलियान वोंग, एपी, बीजिंग, 9 नवंबर, 2012)

पश्चिमी चीन के एक शहर में शुक्रवार 9 नवंबर को हजारों तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन कर चीन के शासन से आज़ाद करने की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विरोध की इस कार्रवाई का समय निश्चित रूप से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अभिजात शीर्ष नेताओं को एक संकेत देने के लिए चुना गया है जो बीजिंग में नए नेतृत्व के चयन के लिए जुट रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर हाईस्कूल के विद्यार्थी थे। प्रदर्शनकारियों ने रोंगवो शहर में मार्च निकालते हुए तिब्बत को आज़ाद करने और अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की वापसी के नारे लगाए। शहर में रहने वाले कई लोगों और बाहर से यहां आने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी है। शहर में रहने वाले एक तिब्बती पेंटर ने कहा, "आज सुबह तो बवाल का माहौल था।"

गौरतलब है कि तिब्बती पठार के एक छोर पर स्थित इस शहर में 600 साल पुराना रोंगवो मठ है। शहर में पिछले महीनों में तनाव बढ़ता जा रहा है और यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था।

22 वर्ष के एक तिब्बती किसान ने बताया कि विरोध प्रदर्शनकारी सुबह चार बजे से ही मठ के पास स्थित स्थानीय हाईस्कूल के पास जुटना शुरू हो गए और जल्दी ही उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। उसने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सैकड़ों किशोर छात्र कर रहे थे और इसमें स्थानीय किसान भी शामिल थे। पेंटर और किसान ने इस संवाददाता से फोन पर बात की और सरकारी दमन के डर से नाम सार्वजनिक न करने का अनुरोध किया।

रोंगवो को चीनी में लोंगवु के नाम से जाना जाता है। लोंगवु के किसी सरकारी अधिकारी या क्विंघई प्रांत में के तहत इस शहर को देखने वाले काउंटी के किसी अधिकारी ने न तो कोई टिप्पणी की है और न ही हमारे फोन कॉल का जवाब दिया है।

एक ऑटो मैकेनिक ने बताया कि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर कड़ी निगाह रखे हुए थी, लेकिन तत्काल किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऑटो मेकैनिक ने अपना नाम न जाहिर करते हुए सिर्फ अपना सरनेम मा बताया।

गौरतलब है कि इस हफ्ते पांच तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है जिनमें से दो रोंगवो के आसपास के इलाके के हैं। इसके बाद इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पिछले एक वर्ष में आत्मदाह की ऐसी 50 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तिब्बतियों का कहना है कि चीन के बढ़ते सख्त धार्मिक और सामाजिक नियंत्रणों के प्रति अपना बढ़ता असंतोष जाहिर करने के लिए लोग इस तरह के कदम उठा रहे हैं।

बीजिंग में पार्टी कांग्रेस में शामिल होने के लिए जुटे तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों ने पत्रकारों से कहा कि उनका मानना है कि आत्मदाह की इन लहर के लिए काफी हद तक दलाई लामा और उनके सहयोगी जिम्मेदार हैं जो उनके मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के लिए लोगों को उकसा रहे हैं।

चीन द्वारा नियुक्त तिब्बत के उप गवर्नर लोबसांग ग्येनकेन ने कहा, "हर कोई यह देख सकता है कि इस तरह की घटनाएं बाहरी तिब्बती ताकतों द्वारा प्रेरित की जा रही हैं। वे आत्मदाह को नायकत्व की कार्रवाई बता रहे हैं और आत्मदाह करने वालों को नायक का दर्जा दे रहे हैं।" ग्येनकेन "स्थिरता बनाए रखने" के प्रभारी बनाए गए हैं। अशांति के दमन के लिए पार्टी ने पुलिसिया कार्रवाई, निगरानी और प्रयासों के लिए यह शब्द गढ़ रखा है। ग्येनकेन ने पार्टी कांग्रेस के उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, "बाहरी तिब्बती ताकतें और दलाई गुट अपने गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दूसरे लोगों का जीवन बलिदान कर रहे हैं।"

पार्टी की धार्मिक नीतियों की तरफदारी करने वाले अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर रहा है, लेकिन तिब्बती मंदिरों और भिक्षुओं को राजनीतिक और देशभक्ति शिक्षा को अपनाना चाहिए। विदेशों में स्थित तिब्बत समर्थक संगठनों का कहना है कि हाल के दिनों में तिब्बत में विरोध प्रदर्शनों का बढ़ना नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे चीनी नेतृत्व

को यह संदेश देना है कि तिब्बती लोग चीनी शासन से तहत नाखुश हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बतियों की लंबे समय से लंबित शिकायतों का तत्काल समाधान करे

(तिब्बत डॉट नेट, 2 नवंबर, 2012)

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त श्रीमती नवी पिल्लई ने शुक्रवार को चीनी प्रशासन से आग्रह किया कि वह लंबे समय से बनी उन शिकायतों का तत्काल समाधान करे जिनकी वजह से तिब्बती इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के आत्मदाह जैसे चरम स्वरूप के प्रदर्शन में चिंताजनक रूप से तेजी आई है। मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि वह "अभिव्यक्ति, संघ बनाने और धर्म की स्वतंत्रता के अपने बुनियादी मानवाधिकारों के इस्तेमाल की चाह रखने वाले तिब्बतियों के खिलाफ लगातार हिंसा के इस्तेमाल के आरोपों को देखकर व्यथित हैं।" उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि "तिब्बत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के दमन और तिब्बतियों के सांस्कृतिक अधिकारों पर अंकुश के लिए ताकत के अतिशय इस्तेमाल, लोगों को नजरबंद करने और उनको गायब कर देने की खबरें आ रही हैं."

इन मामलों में 17 वर्ष की एक लड़की का भी मामला शामिल है जिसे खबरों के मुताबिक बुरी तरह से पीटा गया है और तीन साल तक जेल में बंद रखा गया। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने तिब्बत की आज़ादी और परमपावन दलाई लामा की वापसी की आह्वान करने वाली पुस्तिकाएं वितरित की थीं। कई अन्य लोगों को निबंध लिखने, फिल्म बनाने या तिब्बत के आयोजनों की चीन से बाहर तस्वीरें भेजने के आरोप में चार से सात तक जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मुदकमे के समुचित मानक और हिरासत में लिए गए लोगों के प्रताड़ना और दुर्व्यवहार के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

पिल्लई ने कहा, "मैंने चीन सरकार से इस बारे में कई संदेशों का आदान–प्रदान किया है। लेकिन मानवाधिकारों की रक्षा और हिंसा को रोकने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है। मैंने चीन सरकार से आग्रह किया है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने और अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान करे और सिर्फ अपने इन सार्वभौमिक अधिकारों का पालन करने पर हिरासत में लिए सभी लोगों को रिहा करे।

मानवाधिकार आयुक्त ने तिब्बतियों से यह अपील भी है कि वह विरोध प्रदर्शनों के चरम रूप जैसे आत्मदाह आदि के इस्तेमाल से दूर रहें और उन्होंने वहां के सामुदायिक नेताओं और धर्म गुरुओं से आग्रह किया है कि जीवन को खत्म कर लेने के इस दुःखद चलन को रोकने में मदद के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

उन्होंने कहा, "मैं तिब्बतियों में व्याप्त भारी कुंठा और असंतोष की भावना को समझती हूं जिसकी वजह से उन्हें ऐसे चरम साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन इन भावनाओं को दूर करने के अन्य तरीके भी हैं। सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए और तिब्बतियों को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वे बिना किसी बदले के डर से अपनी भावना को सहज तरीके से व्यक्त कर सकें।"

उच्चायुक्त ने चीन सरकार से यह आग्रह किया कि वह भरोसा बहाली के प्रयासों के तह स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानीकर्ताओं को उस इलाके में दौरा करने और सही हालात का जायजा लेने की इजाजत दे और वहां मीडिया के जाने पर लगी रोक को भी हटाए। उन्होंने याद दिलाया कि विभिन्न मानवाधिकार मसलों को लेकर चीन की आधिकारिक यात्रा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों के 12 अनुरोध लंबित पड़े हैं। इनमें धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता के विशेष प्रतिवेदक की एक रिपोर्ट भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समक्ष चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की नियमित समीक्षा के दौरान चीन ने यह वचन दिया था कि वह विशेष प्रतिवेदकों के साथ सहयोग करेगा। पिल्लई ने चीन सरकार से आग्रह किया कि वह प्रतिवेदकों को चीन जाने का मौका दे।

उन्होंने कहा, "तिब्बत में कभी भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त और मानवाधिकारों के दमन से सामाजिक स्थिरता हासिल नहीं की जा सकती। गहरे निहित मसलों का समाधान किया जाना चाहिए और मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा दी गई सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करे और मानवाधिकारों के मसले पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा पेशकश की जा रही सलाह का लाभ उठाए।"

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने तिब्बत के मसले पर चीन से निम्न सिफारिशें की हैं:

–भोजन के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ओलिवियर डी शटर ने ने सुझाव दिया है कि नोमैड चरवाहों (तिब्बती जनसंख्या का बहुसंख्यक हिस्सा) के गैर स्वच्छिक पुनर्वास पर रोक लगाई जाए और उन्होंने इस बारे में सार्थक राय लेने का आग्रह किया है।

–सभी तरह के भेदभाव को खत्म करने की संयुक्त राष्ट्र की समिति (सीईआरडी) ने चीन को यह सुझाव दिया है कि किसी भी ऐसी नीति या प्रोत्साहन पेशकश की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे स्वायत्त अल्पसंख्यक क्षेत्रों के जनसंख्या घटक में भारी बदलाव आता हो। सीईआरडी ने यह सुझाव भी दिया है कि सरकारी पक्ष को अंतर नस्लीय हिंसा जैसी मार्च 2008 में शुरु

हुई अशांति की जड़ और इस परिस्थिति के और बिगड़ जाने की वजह पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

–नवंबर, 2008 में संयुक्त राष्ट्र प्रताड़ना रोधी समिति ने सिफारिश की थी कि मार्च 2008 के आसपास की घटनाओं की चीन व्यापक और स्वतंत्र तरीके से जांच करे और इस जांच में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ बल के अतिशय इस्तेमाल, खासकर कार्डजे काउंटी, नाबा काउंटी और ल्हासा के खिलाफ और गिरफ्तार एवं हिरासत में लिए गए लोगों के प्रताड़ना और उनके साथ दुर्व्यवहार के आरोपों की।

पिल्लई ने कहा, "मेरा कार्यालय उस इलाके के इन सभी मसलों के हल के लिए और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक सहयोग को तैयार है।

एक हफ्ते में तीन आत्मदाह देखने वाले काउंटी में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 11 नवंबर)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हर पांच साल पर होने वाली 18वीं कांग्रेस में अगले दशक के लिए चीन के लिए पांचवीं पीढ़ी के नए नेता की घोषणा की तैयारी के बीच तिब्बतियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए आत्मदाह की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इन आत्मदाह की घटनाओं से दुःखी क्विंघई प्रांत के रेबगोंग काउंटी में स्थित रोंगवो शहर में गत 8 एवं 9 नवंबर को हजारों तिब्बती विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके अलावा शीनिंग शहर के क्विंघई नेशनलिटीज यूनिवर्सिटी में भी बड़ी संख्या में जुटकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किए हैं।

धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) ने 9 नवंबर को बताया कि माल्हो प्रशासनिक क्षेत्र के चार काउंटी के स्कूलों के 5,000 तिब्बती विद्यार्थियों, माल्हो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थी और माल्हो वोकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने मिलकर 9 नवंबर को सुबर 5 बजे से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्यार्थी सभी राष्ट्रीयताओं के बीच समानता लाने, भाषा की स्वतंत्रता, दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने जैसे कई नारे लगा रहे थे और पूरी भीड़ ने शहर में मार्च निकालने के बाद डोलमा चौक पर पहले से जमा विरोध प्रदर्शन कर रहे और प्रार्थना कर रहे तिब्बतियों के साथ शामिल हो गए। डोलमा चौक उस रोंगवो मठ के सामने ही है जहां 8 नवंबर को 18 वर्ष के भिक्षु कालसांग जिन्पा ने चीन सरकार का विरोध करते हुए आत्मदाह कर लिया था। खबरों के मुताबिक विद्यार्थियों ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त वाले एक सरकारी कार्यालय कॉम्प्लेक्स के बाहर भी प्रदर्शन किया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने वालों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात को रोक दिया था।

इसके पहले 8 नवंबर को करीब 700 स्कूली बच्चों ने रेबगोंग काउंटी के ही दोवा टाउनशिप में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके एक दिन पहले ही दोवा की निवासी 23 वर्षीय महिला और एक बच्चे की मां तामडिन सो ने चीन सरकार के विरोध में आत्मदाह कर लिया था। बताया जाता है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी नारे लगाते हुए स्थानीय सरकारी कार्यालयों की तरफ बढ़े। खबरों के मुताबिक भीड़ ने एक स्कूल की इमारत और शहर के सरकारी कार्यालय से लाल तारों वाला चीन झंडा उतारकर फेंक दिया।

उसी दिन दोपहर में विद्यार्थियों और स्थानीय निवासियों की एक भीड़ (जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं) ने रेबगोंग काउंटी की तरफ से आ रहे सेना के सात ट्रकों के बेड़े को दोवा शहर में घुसने से रोक दिया। हालांकि, इन विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना ने कोई कार्रवाई नहीं की।

रेडियो फ्री एशिया की खबर के मुताबिक 9 नवंबर को क्विंघई प्रांत की राजधानी शिनिंग में स्थित क्विंघई नेशनलिटीज यूनिवर्सिटी के करीब एक हजार विद्यार्थियों ने जुटकर चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शहीद हो जाने वाले तिब्बतियों के लिए प्रार्थनाएं कीं। खबरों के मुताबिक विद्यार्थियों ने शाम 6:10 से 7:20 तक मोमबत्तियां जलाईं और इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बार–बार यह रैली खत्म करने के अनुरोध पर वे वापस चले गए।

दलाई लामा की तस्वीर रखने पर पाबंदी आत्मदाह के लिए उकसाने की वजह बनी

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 14 नवंबर)

दलाई लामा के तस्वीर रखने पर रोक लगने की जानकारी देता और तिब्बतियों से 'अलगाववादी ताकतों' का विरोध करने को कहता चीन सरकार का एक पोस्टर 23 वर्ष की एक बच्चे की मां तामडिन सो द्वारा 7 नवंबर को आत्मदाह के लिए उकसाने की तात्कालिक वजह बन गया। तामडिन सो ने क्विंघई प्रांत के माल्हो प्रशासनिक क्षेत्र के रेबगोंग काउंटी स्थित गेमार बाजार इलाके में आत्मदाह कर लिया। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने 13 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर बताया है कि चीन सरकार ने सभी मठों में दलाई लामा की किसी भी तरह की तस्वीर रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।

चीन सरकार द्वारा जगह–जगह लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि तिब्बतियों की सभी धार्मिक गतिविधियां पूरी

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख से

1. परमपावन दलाई लामा का 23 नवंबर, 2012 को केरल के तिरुअनंतपुरम में भव्य स्वागत किया तीर्थ के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। (फोटोः ओएचएचडीएल/जेरेमी रसेल)
2. धर्मशाला में 17 नवंबर, 2012 को टीसीवी स्कूल के देक्यी सेरिंग हॉल में आयोजित दूसरे कि परमपावन दलाई लामा। 16 से 18 नवंबर, 2012 तक आयोजित इस बैठक में 43 देशों के करी
3. जापान के टोक्यो स्थित जापानी संसद भवन में 13 नवंबर, 2012 को सांसदों को संबोधित
4. जापान की टोक्यो स्थित संसद में 13 नवंबर, 2012 को परमपावन दलाई लामा का स्वागत
5. धर्मशाला में 16 नवंबर, 2012 को टीसीवी स्कूल के हॉल में अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक सं डॉ. लोबसांग सांगे। (फोटोः नोर्बू वांग्याल, फायूल)
6. जापान के ओकिनावा शहर में स्थित केनरित्सु बुडोकान हॉल में गत 11 नवंबर को "कठिनाई से को संबोधित करने से पहले उपस्थित लोगों का अभिवादन करते परमपावन दलाई लामा।
7. कैलिफोर्निया के व्यस्त वेस्टफील्ड–सैनफ्रांसिस्को सेंटर के सामने तिब्बती राष्ट्रीय झंडे और रहे थे कि वे 'चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करें' और तिब्बत में चीनी शासन का विरोध युवा कांग्रेस द्वारा किया गया। (फोटोः एसएफआरटीवाईसी)
8. तिब्बत के आमदो प्रांत में रेबगोंग के रोंगवो मठ के बाहर 9 नवंबर, 2012 को शांतिपूर्ण प्र
9. पूर्वी तिब्बत के कार्जे में परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने और तिब्बत को आज़ाद
10. धर्मशाला में 1 से 4 नवंबर, 2012 को आयोजित पहले धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिव

जानकारी देतीं फिल्म निर्माता जेनिफर फॉक्स।

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

कैमरे की आंख से

रम में भव्य स्वागत किया गया। दलाई लामा यहां वर्कला स्थिति शिवगिरी मठ के 80वें शिवगिरी वार्षिक
जेरेमी रसेल)

में आयोजित दूसरे विशेष अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक संगठनों की बैठक में आए लोगों को संबोधित करते
क में 43 देशों के करीब 200 तिब्बत समर्थक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। (फायूल फोटोः नोर्बू वांग्याल)
सांसदों को संबोधित करते परमपावन दलाई लामा। (फोटोः जापान स्थित तिब्बत कार्यालय)
ाई लामा का स्वागत करते जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे। (फोटोः जापान स्थित तिब्बत कार्यालय)
य तिब्बत समर्थक संगठनों की दूसरी विशेष बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिक्योंग

(5)

नवंबर को "कठिनाई से उबरने की ताकत और भविष्य की युवा पीढ़ी से संवाद" विषय पर आयोजित व्याख्यान
पावन दलाई लामा। (फोटोः जापान स्थित तिब्बत कार्यालय)
ती राष्ट्रीय झंडे और तख्तियां लेकर जमा तिब्बती और उनके समर्थक। यह लोग खरीदारों से आग्रह कर
ो शासन का विरोध करें। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन 22 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को रीजनल तिब्बतन

012 को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे स्कूली बच्चे। (फोटोः टीसीएचआरडी)
तिब्बत को आज़ाद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे तिब्बती।
शनल फिल्म फेस्टिवल में उपस्थित लोगों को फिल्म निर्माण की कुछ प्रमुख चुनौतियों और तकनीक की?

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

तरह से चीन सरकार के नियमों के दायरे में होनी चाहिए और मठों एवं भिक्षुणी मठों (ननरी) में कम उम्र के लड़के–लड़कियों को शामिल करने पर पूरी तरह से रोक है। बताया जा रहा है कि चीन सरकार ने "मातृभूमि की एकता को बनाए रखने और दलाई गुट की अलगवाववादी गतिविधियों से निपटने" के नाम पर यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।

तामडिन सो ने दोवा कस्बे में इस तरह का एक पोस्टर देखा और इसे देखकर वह गुस्से एवं दुःख से भर गईं। वह वहां अपने पिता के साथ एक माह पहले ही गई थीं। उनके पिता तामडिन क्याब ने तिब्बतियों से निवेदन किया है कि वे उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि उनका जन्म आज़ाद तिब्बत में हो और उसे दलाई लामा को देखने एवं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो।

तिब्बती फिल्म निर्माता गोलोग जिग्मे ग्यात्सो फिर से गिरफ्तार किए गए

(फ़ायूल, 5 नवंबर)

तिब्बती भिक्षु गोलोग जिग्मे ग्यात्सो को चीनी पुलिस प्रशासन ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। ग्यात्सो ने फिल्म निर्माता धोनढुप वांगछेन की डॉक्यूमेंटरी फिल्म "भय को पीछे छोड़ा" (लीविंग फियर बिहाइंड) की गोपनीय तरीके से शूटिंग में मदद की थी। सितंबर माह से ही उनकी गिरफ्तारी की आशंका जाहिर की जा रही है, जब वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए।

फायूल से बात करते हुए दक्षिण भारत में रहने वाले तिब्बती सरता सुलत्रिम वूएजर ने इस बात की पुष्टि की कि गोलोग जिग्मे को चीनी सुरक्षा कर्मियों ने तब फिर से गिरफ्तार कर लिया जब 20 सितंबर को वह तिब्बत के आमदो में लांझू से सोए वापस जा रहे थे। उनको फिर से गिरफ्तार करने की वजह पता नहीं चल पाई है। इसके पहले इस महीने चीनी प्रशासन ने ग्यात्सो को मठ का अपना कमरा खाली करने का आदेश दिया था और बाद में इस कमरे को जमींदोज कर दिया गया।

वूएजर ने बताया, "5 सितंबर को स्थानीय चीनी प्रशासन ने ग्यात्सो को मठ का कमरा खाली करने का आदेश दिया था और कहा था कि इसकी मरम्मत का काम किया जाना है। लेकिन ग्यात्सो द्वारा कमरे खाली किए जाने के बाद ही चीनी प्रशासन के लोग भारी मशीनें लेकर आए और उन्होंने पूरे मकान को जमींदोज कर दिया।"

अक्टूबर की शुरुआत में न्यूयॉर्क स्थित मीडिया अधिकार निगरानी संगठन कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने ग्यात्सो के गायब होने पर चिंता जताई थी। सीपीजे एशिया के कार्यक्रम समन्वयक बॉब डिएट्ज ने कहा था, "हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिग्मे ग्यात्सो कहां पर हैं, क्योंकि उन्हें पहले भी एक फिल्म बनाने के लिए प्रताड़ित किया जा चुका है और हिरासत में लिया गया है।"

आत्मदाह करने वालों ने परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाने और तिब्बतियों को आज़ादी देने की मांग की है. चीन में अमेरिकी राजदूत गैरी लॉक ने तिब्बत में जारी आत्मदाह की अभूतपूर्व लहर पर 27 नवंबर को फिर से अपनी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, "इस पूरे हालात, तिब्बती इलाकों में बढ़ रहे तनाव, आत्मदाह करने वालों की दुःखद रूप से बढ़ती संख्या और निश्चित रूप से सभी स्तरों पर चीन सरकार की नीतियों को लेकर अमेरिका को भारी चिंता है। हम सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर चीनियों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार करें जिनसे तिब्बती जनता की भाषाई पहचान, सांस्कषतिक पहचान और उनकी धार्मिक पहचान को खतरा होता हो।"

आत्मदाह करने वालों ने परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाने और तिब्बतियों को आज़ादी देने की मांग की है. चीन में अमेरिकी राजदूत गैरी लॉक ने तिब्बत में जारी आत्मदाह की अभूतपूर्व लहर पर 27 नवंबर को फिर से अपनी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, "इस पूरे हालात, तिब्बती इलाकों में बढ़ रहे तनाव, आत्मदाह करने वालों की दुःखद रूप से बढ़ती संख्या और निश्चित रूप से सभी स्तरों पर चीन सरकार की नीतियों को लेकर अमेरिका को भारी चिंता है। हम सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर चीनियों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार करें जिनसे तिब्बती जनता की भाषाई पहचान, सांस्कषतिक पहचान और उनकी धार्मिक पहचान को खतरा होता हो।"

उन्होंने कहा, "अब ऐसा अक्सर हो रहा है। तिब्बती पत्रकारों को बिना किसी उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और ग्यात्सो का गायब होना इस बात की याद दिलाता है कि जो रिहा कर दिए जाते हैं उनके भी लगातार फिर से गिरफ्तारी का डर बना रहता है।"

ग्यात्सो को सबसे पहले मार्च 2008 में लाबरांग टाशी से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सात महीने तक कैद में रखा गया जिस दौरान उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया और पिटाई की गई। इसके बाद उन्हें मार्च, 2009 में फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार उन्हें 40 दिन तक हिरासत में रखा गया। इसके बाद से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है।

ग्यात्सो ने धोनढुप वांगछेन की उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म "लीविंग फियर बिहाइंड" की गोपनीय तरीके से शूटिंग में मदद की थी। इस फिल्म में बीजिंग में वर्ष 2008 ओलम्पिक खेलों की तैयारी के दौरान चीन में रहने वाले तिब्बतियों के जीवन पर रोशनी डाली गई है।

इस फिल्म में तिब्बतियों के साथ कई इंटरव्यू लिए गए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि चीन ने किस तरह से तिब्बती संस्कषति को नष्ट कर दिया है, धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन किया है और निर्वासित तिब्बती नेता परमपावन दलाई लामा के प्रति अब भी किस तरह से लोगों की आस्था को डिगाया नहीं जा

सका है। इस फिल्म को चोरी से पहले तिब्बत से बाहर भेजा गया और फिर दुनिया भर में रिलीज किया गया।

फिल्म बनाने के लिए छह साल कारावास की सजा भुगत रहे धोनढुप वांगछेन को सीपीजे 2012 के इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवॉर्ड के विजेताओं में से एक चुना गया है। यह साहसिक पत्रकारिता के लिए हर साल दिया जाने वाला अवॉर्ड है। जिग्मे ग्यात्सो का जन्म 1969 में खम के कार्डजे क्षेत्र में गोलोग सरता में हुआ था।

दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह किया, संख्या 89 तक पहुंची

(तिब्बत डॉट नेट, 29 नवंबर)

तिब्बत में दो अलग–अलग घटनाओं में दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। इस तरह आत्मदाह करने वालों की कुल संख्या 89 तक पहुंच चुकी है जिसमें अकेले नवंबर माह में आत्मदाह करने वाले 27 लोग शामिल है।

पूर्वोत्तर तिब्बत में कान्हलो के सोए शहर में 21 वर्ष के बेंडे खार 28 नवंबर को आत्मदाह कर शहीद हो गए। आत्मदाह से पहले उन्होंने परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाने, सभी तिब्बती राजनीतिक बंदियों को रिहा करने, धर्म और भाषा की आज़ादी और तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को बचाने का आह्वान करते हुए नारे लगाए।

इसके अलावा कानल्हो के ही लुछु शहर में गत 29 नवंबर को 31 वर्ष के सेरिंग नामग्याल ने एक सरकारी कार्यालय के बाहर खुद को आग के हवाले कर लिया। वह लुछु क्षेत्र के जामत्सा लोत्सो गांव के रहने वाले थे। वह अपने पीछे मां–बाप, अपनी युवा पत्नी और 7 एवं 3 वर्ष की दो छोटी बेटियों को छोड़ गए हैं।

आत्मदाह करने वालों ने परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाने और तिब्बतियों को आज़ादी देने की मांग की है. चीन में अमेरिकी राजदूत गैरी लॉक ने तिब्बत में जारी आत्मदाह की अभूतपूर्व लहर पर 27 नवंबर को फिर से अपनी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, "इस पूरे हालात, तिब्बती इलाकों में बढ़ रहे तनाव, आत्मदाह करने वालों की दुःखद रूप से बढ़ती संख्या और निश्चित रूप से सभी स्तरों पर चीन सरकार की नीतियों को लेकर अमेरिका को भारी चिंता है। हम सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर चीनियों से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वे अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार करें जिनसे तिब्बती जनता की भाषाई पहचान, सांस्कर्षतिक पहचान और उनकी धार्मिक पहचान को खतरा होता हो।"

चालीस साल की मैत्री तपस्या विजय क्रान्तिः तिब्बत का एक पुराना, भरोसेमंद दोस्त

भेंटवार्ता : गेलेक नामग्याल

दुनिया भर में फैले तिब्बती समाज के मित्रों की बिरादरी में भारतीय पत्रकार, फोटोग्राफर और तिब्बतशास्त्री विजय क्रान्ति का अपना एक अलग स्थान है। 1972 में एक पत्रकार के रूप में तिब्बत के साथ शुरू हुआ उनका रिश्ता इस साल नवंबर में 40 साल पूरे कर रहा है। इस बीच वह तिब्बती मामलों के एक विशेषज्ञ के रूप में उभरने के साथ–साथ तिब्बत के एक भरोसेमंद दोस्त भी सिद्ध हुए हैं।

इंडिया टुडे, बीबीसी, वॉयस ऑफ अमेरिका, जर्मन रेडियो, आज तक टीवी और ज़ी न्यूज़ टीवी जैसे कई सम्मानित संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रहने के अलावा वह तीस साल तक 'तिब्बत देश' के अवैतनिक और स्वयंसेवी संपादक भी रह चुके हैं। 1979 में उनकी पहल पर तिब्बत–देश का प्रकाशन आरंभ किया गया। तब से 2010 तब वह इससे जुड़े रहे हैं।

तिब्बत के साथ 40 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर श्री विजय क्रान्ति की तिब्बती फोटोग्राफी पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय फोटो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अगले दो साल में दुनिया भर के कई देशों में तिब्बत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली उनकी लगभग एक दर्जन फोटो प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। इस फेस्टिवल का नाम है 'बुद्धाज़ होम कमिंग' (बुद्ध की घर वापसी)। इस संदर्भ में तिब्बत–देश के गेलेक नामग्याल के साथ उनकी भेंटवार्ता यहां प्रस्तुत है।

गेलेक नामग्याल – तिब्बत के साथ आपके इस लंबे संबंध की शुरूआत कैसे हुई? चालीस साल तक चलने वाली इस दोस्ती के बारे में कुछ बताइए?

विजय क्रान्ति – 1972 में हिंदी की प्रसिद्ध समाचार पत्रिका 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' ने मुझे तिब्बती शरणार्थियों पर एक आवरण कथा लिखने को कहा। तब मैं पत्रकारिता में केवल दो साल का बच्चा था। इस एसाइनमेंट में दलाई लामा जी का इंटरव्यू और लेख के लिए आवश्यक फोटो उपलब्ध कराना भी शामिल था। आम तौर पर हम पत्रकार लोग सैंकड़ों विषयों पर लिखते हैं। लेकिन ज्यादातर लेखों के छपने के बाद हमें न तो उस विषय पर दोबारा लिखने का मौका मिलता है और न इच्छा ही होती है। लेकिन तिब्बती लोगों से मिलने और तिब्बती जनता के संघर्ष को समझने का अनुभव कुछ और ही था। खासकर शरणार्थी तिब्बती युवाओं की अपने देश की आजादी के प्रति लगन और आस्था ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और दलाई लामा जी की सादगी, विद्वत्ता, अपने देश के प्रति उनकी आस्था और अहिंसा की शक्ति पर उनके विश्वास ने तो मुझे ऐसा मोहा कि आज भी मैं उनका मुरीद हूं।

अपने इस पहले अनुभव के बाद तिब्बत के बारे और जानने की मेरी रुचि इतनी बढ़ती चली गई कि आज 40 साल बाद भी लगता है कि अभी तो और बहुत कुछ जानना समझना बाकी है।

गेलेक – यह तो रही पत्रकार के रूप में व्यावसायिक बात। तिब्बत के साथ आपके भावुक रिश्तों के पीछे भी क्या पत्रकारिता ही रही?

वि क्रा – नहीं। भावुक संबंध तो बहुत निजी मामला है। असल में मैं भी एक शरणार्थी परिवार का सदस्य हूं। मेरे माता–पिता को भी तिब्बतियों की तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में अपना घर छोड़कर अचानक भागना पड़ा था। वे ऐसे समय में शरणार्थी हुए जब भारत–पाक विभाजन की आग थम चुकी थी और जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन चुका था। मैं भी दिल्ली की एक रिफ्यूजी स्लम में पैदा हुआ था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से अपने माता पिता के निर्वासन वाले दर्द को मुझे बहुत करीब से छूने के सैंकड़ों अवसर मिले। शायद यही कारण था कि तिब्बती शरणार्थी समाज के दर्द को समझना और उससे प्रभावित होना मेरे दिल के लिए बहुत स्वभाविक था। शायद यह रिश्ता दर्द का रिश्ता भी है।

गेलेक– तिब्बत के बारे में आपकी फोटोग्राफी को दुनिया भर में बहुत सम्मान मिला है। अपनी फोटोग्राफी के बारे में कुछ बताइए।

वि क्रा– सच कहूं तो तिब्बत के इस पहले लेख के लिए मुझे फोटोग्राफी बहुत मजबूरी में करनी पड़ी थी। लेकिन इस मजबूरी ने मुझे एक गंभीर फोटोग्राफर बना दिया। पत्रिका को ढेर सारे फोटो चाहिए थे, लेकिन संपादक जी अपना फोटोग्राफर भेजने की स्थिति में नहीं थे। किसी अच्छे फोटोग्राफर को अपने खर्चे पर दिल्ली से धर्मशाला ले जाना उन दिनों की अर्थव्यवस्था में मेरे लिए संभव ही नहीं था। लिहाज़ा एक दोस्त से कैमरा उधार मांगकर मैंने खुद ही यह काम किया। लेकिन फोटो देखकर साप्ताहिक के ले–आउट कलाकार तूलिकी जी (अब स्वर्गीय) इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस आवरण कथा के साथ मेरे 18 फोटो छापे। बाद में दोस्ती होने के बाद वह बहुत अच्छे इंसान और स्नेहशील गुरू भी सिद्ध हुए। उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन में मैंने फोटोग्राफी को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। आज उनके आशीर्वाद से तिब्बत पर मेरे काम को बहुत सम्मान मिला है।

गेलेक – इस फोटो फेस्टिवल का लक्ष्य क्या है?

वि क्रा – तिब्बती शरणार्थी समाज ने भारत आकर अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को एक गंभीर राष्ट्रीय संकट और कठिन हालात के बावजूद जिस प्रभावी तरीके से जीवित किया वैसा दुनिया के ताजा इतिहास में कभी नहीं हुआ। और यह सब दलाई लामा जी की दूरदृष्टि, तिब्बती शरणार्थी समाज की लगन और भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए दोस्ताना वातावरण और सुविधाओं का नतीजा है। पिछले पचास साल में चीन सरकार ने तिब्बत की संस्कृति, जीवन शैली और तिब्बती पहचान के लगभग हर प्रतीक को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद आज तिब्बती शरणार्थी समाज ने भारत को दुनिया में तिब्बती संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। मुझे गर्व है कि एक फोटोग्राफर के नाते मुझे 40 साल तक तिब्बती समाज की इस निर्माण यात्रा को बहुत नजदीक से देखने और रिकार्ड करने का अवसर मिला। यही कारण है कि मेरा फोटो फेस्टिवल तिब्बती शरणार्थी समाज, दलाई लामा और भारतीय जनता को समर्पित है। यह फेस्टिवल दुनिया के सामने इस सफलता को कलात्मक अंदाज़ में पेश करने का प्रयास है।

गे ना – आपने अपने फोटो फेस्टिवल का नाम 'बुद्धाज़ होम कमिंग' क्यों रखा है?

वि क्रा – दलाई लामा जी के भारत आने से बौद्ध धर्म को एक नया जीवन मिला है। यही कारण है कि परमपावन दलाई लामा जी का भारत आना लगभग ऐसा ही है मानो भगवान बुद्ध हजारों साल बाद फिर से अपने घर लौटकर आ गए हैं। 'बुद्धाज़ होम कमिंग' यानी 'बुद्ध की घर वापसी' इसी भावना को पेश करता है।

गेलेक – आपने पिछले चार दशक में भारत और दुनिया के कई देशों में अपनी फोटो प्रदर्शनियां पेश की हैं। आपकी फोटोग्राफी का मुख्य लक्ष्य क्या है। यह फेस्टिवल किस मायने में अलग है?

गेलेक – पहले वाली प्रदर्शनियां मुख्य रूप से तिब्बती शरणार्थी समाज और चीनी कब्जे में मौजूदा तिब्बत जीवन के किसी एक पक्ष की एक कलात्मक छवि पेश करने पर केंद्रित थीं। यह फेस्टिवल तिब्बती संस्कृति की खूबसूरती के साथ–साथ तिब्बती जनता की इस अनूठी सफलता की एक व्यापक कहानी पेश करने का प्रयास है। दुनिया भर में इस श्रंखला के पूरा होने के बाद हम इस पूरे सेट को भारत में एक 'तिब्बत फोटो महोत्सव' की तरह पेश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि यह भारतीय फोटोग्राफी के हाल ही के इतिहास का सबसे बड़ा वन–मैन–शो होगा।

गेलेक – तिब्बत पर आपने यह फोटोग्राफी किस तरह से की है?

गेलेक – 1972 के अपने तिब्बती फोटोग्राफी अनुभव के बाद पहली बार मेरा अपने भीतर के फोटोग्राफर से साक्षात्कार हुआ। इस अनुभव से मुझे तिब्बती संस्कृति की विशालता और सुंदरता का भी अंदाज़ हुआ। तब से मैंने फोटोग्राफी को गंभीरता से लेने और तिब्बती जीवन का विस्तार से फोटो अध्ययन करने का फैसला किया। पिछले 40 साल के दौरान मैं निर्वासन में रह रहें अधिकांश तिब्बती समाजो और शरणार्थी बस्तियों में जाकर फोटोग्राफी करता रहा हूं। तिब्बत की असली हालत को एक फोटोग्राफर की तरह दर्ज करने के लिए मैं कई बार तिब्बत के भीतर अपने फोटो–एक्सपीडिशन भी कर चुका हूं।

गेलेक– आपको तिब्बत की यात्राओं के दौरान चीन सरकार से डर नहीं लगा? सुना है आप जैसे पत्रकार के लिए यह बहुत खतरनाक भी हो सकता है?

वि क्रा – सच कहूं तो डर तो लगता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार का विदेशी पत्रकारों के प्रति रवैये का इतिहास बहुत सुखद नहीं है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं यह भी जानता हूं कि जब तक मैं जोखिम नहीं उठाउंगा, मेरा काम बाकी लोगों की तरह 'सामान्य' ही रहेगा। कुछ खास पाने के लिए जोखिम उठाने का जज्बा चाहिए। सौभाग्य से मुझमें इतना पागलपन तो है ही।

गेलेक – तिब्बत पर आपकी फोटोग्राफी किस मायने में महत्वपूर्ण है?

वि क्रा – असली महत्व तो केवल भविष्य ही बताएगा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैंने तिब्बती शरणार्थी समाज के उन ऐतिहासिक 50 वर्षों में से 40 वर्षों तक उनके जीवन की फोटोग्राफी की है जिसे तिब्बत की आने वाली पीढ़ियां 'राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के ऐतिहासिक काल' के रूप में याद करेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस काल के कलात्मक डाकुमेंटेशन के मेरे काम को कुछ मायनों में तो उपयोगी माना ही जाएगा।

गेलेक – 'तिब्बत देश' तिब्बत के बारे में पहली और एकमात्र समाचार पत्रिका है। आप इसके संस्थापक और 30 साल तक संपादक रहे हैं। कैसा अनुभव था यह पत्रिका प्रकाशित करना?

वि क्रा – तिब्बत के संपर्क में आने और भारतीय हितों पर तिब्बत की स्थिति के गंभीर प्रभाव को समझने के बाद मुझे लगातार यह बात सालती थी कि आम भारतीय को, खासकर बुद्धिजीवियों और राजनेताओं को तिब्बत के मामले में ताजा जानकारी नहीं है। भारतीय पाठकों तक तिब्बत की जानकारी पहुंचाने वाली कोई पत्रिका नहीं है। यही सोचकर 1979 में मैंने कुछ तिब्बती युवा मित्रों के साथ मिलकर 'तिब्बत देश' की शुरूआत की। काम बहुत रोचक लेकिन बहुत कठिन था। उन दिनों तिब्बत पर समाचार सामग्री इकट्ठा करना, हिंदी में कंपोजिंग कराना और कई रात प्रिंटिंग प्रेस में देर तक बैठकर ले–आउट और प्रूफ पढ़ना शरीर को तो तोड़ देता था लेकिन तिब्बत के प्रति उत्साह को बहुत मजबूत करता था। दिन में अपनी नौकरी और खाली समय में एक स्वयंसेवी संपादक का काम करना आसान तो नहीं था लेकिन फिर भी 30 साल तक निभाया। पाठकों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं और पत्रिका की उपयोगिता के बारे में विद्वानों से मिलने वाली टिप्पणियां इस उत्साह को बनाए रखने के लिए टॉनिक का काम करती थीं। इसलिए यह सब किसी मां के प्रसव की पीड़ा जैसा दर्दभरा मगर आनंददायी रहा। पंजाबी के महानकवि शिव बटालवी ने इस तरह के दर्द के लिए 'मिट्ठा अते दुखावां' (मीठा और कष्टदायी) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है।

गेलेक – तिब्बत के संदर्भ में 'तिब्बत देश' की भूमिका और योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे?

वि क्रा – संपादक के तौर पर मेरी नीति बहुत स्पष्ट थी। पत्रिका के हर अंक का उद्देश्य था अपने पाठकों को तिब्बत के भीतर, चीन में, विश्वमंच पर, तिब्बती शरणार्थी समाज में और भारत में होने वाली तिब्बत संबंधी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की ताजा जानकारी देना। इसलिए मैं महीना भर ऐसे हर समाचार पर नजर रखता था और समाचारपत्रों की कतरनें, प्रेस वक्तव्य और ऐसी हर तरह की सामग्री इकट्ठा करता रहता था जो आगामी अंक के लिए उपयोगी हो सकती थीं। कुल मिलाकर पत्रिका का हर अंक तिब्बत के ताजा घटने वाले इतिहास का एक सरल अध्याय जैसा होता था। इसी तरह हर महीने का मेरा संपादकीय भी बीते महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटना या मुद्दे पर अपने पाठकों को नई जानकारी देने और तिब्बत की ताजा स्थिति को भारतीय नजरिए से समझने में सहयोग देने पर केंद्रित रहता था। आषा है कि यह पत्रिका भविष्य में अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती रहेगी।

गेलेक – इन दिनों तिब्बत में चल रही आत्मदाह की घटनाओं के बारे में आपकी क्या राय है?

वि क्रा– ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पिछले लगभग डेढ़ साल में आज तक (26 नवंबर, 2012) तिब्बती युवा आत्मदाह कर चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में आत्मदाह दिखाते हैं कि तिब्बत में चीनी शासन से तिब्बती जनता कितनी दुखी है। पर दुख की बात है कि इन युवाओं की बात सुनना तो दूर रहा, चीन सरकार अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है अपने आप को सभ्य और लोकतंत्र के पैरोकार कहने वाली सरकारें और संगठन इस सवाल पर चीन के सामने मुंह खोलने को भी तैयार नहीं हैं।

लेकिन तिब्बत में चल रहे आत्मदाह के इस सिलसिले ने दुनिया के सामने तिब्बत की असली हालत को स्पष्ट कर दिया है। इन आत्मदाहों ने चीन सरकार के इस झूठ को बेनकाब कर दिया है कि तिब्बती जनता चीनी राज में खुश है या तिब्बत में सब कुछ ठीक–ठाक है। दूसरे, आत्मदाह करने वाला हर युवा तिब्बत की आजादी और दलाई लामा की तिब्बत वापसी की मांग कर रहा था। यह दिखाता है कि चीनी उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने की तिब्बती जनता की इच्छा आज साठ साल बाद भी न केवल कायम है, बल्कि पहले से यह और तेज हुई है। तीसरे, आत्मदाह करने वाले ये सभी युवा ऐसे हैं जिनके माता पिता ने भी अपने जीवन काल में न तो आजाद तिब्बत को देखा और न दलाई लामा को। जिंदगी भर तीन पीढ़ियों तक चीनी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पर पाले जाने के बावजूद तिब्बती नागरिक यह मानने को तैयार नहीं हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है।

चौथे, आत्मदाह की 90 प्रतिशत घटनाएं 'तिब्बती स्वायत्त शासन क्षेत्र' (टार) से बाहर ऐसे तिब्बती इलाकों में हुई हैं जिन्हें चीन सरकार 'तिब्बत' का हिस्सा नहीं मानती। 1951 में तिब्बत पर सैनिक कब्जे के बाद इन इलाकों को चीन ने तिब्बत से काटकर अपने सिचुआन, युन्नान, चिंघाई और गांसू प्रांतों में मिला दिया था। यह दिखाता है कि पूरा तिब्बत चीनी उपनिवेशवाद से दुखी है और चीनी कब्जे से मुक्ति पाना चाहता है।

और पांचवीं बात यह है कि आत्मदाह जैसा घोर कष्टदायी रास्ता चुनने के बावजूद एक भी तिब्बती युवा ने वहां लाकर जबरन बसाए गए किसी चीनी नागरिक पर चाकू, बंदूक या बम से हमला नहीं किया। यह तिब्बती जनता के मन में दलाई लामा द्वारा सिखाई गई अहिंसा में उनकी आस्था की मजबूती दिखाता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में आत्मदाहों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की सरकारें तिब्बत के लिए आवाज उठाने से मना कर देती हैं तो वे दुनिया भर में न्याय की मांग करने वाले लोगों, समाजों और संगठनों को यही संदेश दे रही हैं कि उनकी बात केवल तभी सुनी जाएगी जब वे हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। मुझे लगता है कि दुनिया के आजाद देशों में रहने वालों के लिए ऐसी स्थिति बहुत शर्मनाक है।

तिब्बत की संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करें, परमपावन ने अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक संगठनों की बैठक में कहा

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 17 नवंबर, 2012)

अंतरराष्ट्रीय तिब्बत समर्थक समूह की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए परमपावन दलाई लामा ने शनिवार, 17 नवंबर को कहा कि तिब्बत की विशिष्ट संस्कृति और नाजुक पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। परमपावन दलाई लामा ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र और आज़ादी की बयार बह रही है। इसलिए चीन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो उसे आज़ादी और न्याय के इस चलन को अपनाना ही होगा।

तिब्बत समर्थक संगठनों की विशेष बैठक में परमपावन द्वारा दिया गया पूरा भाषण इस प्रकार हैः

तिब्बत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे दौर में आप सब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोग हमारे लिए यहां अपनी गहरी चिंता और समर्थन जताने के लिए आए हैं। हमारे समर्थक सिर्फ तिब्बत समर्थक नहीं बल्कि न्याय समर्थक और अहिंसा समर्थक हैं।

तिब्बती संघर्ष अहिंसक संघर्ष रहा है। वैश्विक स्तर पर ऐसे बहुत से समुदाय हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि उनका उद्देश्य उत्तम होने के बावजूद वे अपनी समस्या को सुलझाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

इसलिए आपका समर्थन हमारे लिए प्रोत्साहन जैसा है और व्यावहारिक स्तर पर अहिंसक समर्थन को ही कारगर होना चाहिए, अन्यथा लोग यह कहने लगेंगे कि अहिंसा निरर्थक होती है।

कई बार लोग एक परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। हिंसा गुस्से का नतीजा होती है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता तो आप बंदूक का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर कठोरता से अहिंसक तरीकों को सफल होना चाहिए। काफी संख्या में चीनी लोकतांत्रिक आंदोलनकारियों ने भी हमारे आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई है।

तिब्बती मसले को तीन मुख्य पहलुओं में बांटा जा सकता हैः

1.पारिस्थितिकीः वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के द्वारा तिब्बत के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। मेरे एक भारतीय मित्र का कहना है कि तिब्बत काफी उच्च अक्षांश पर है और वहां की जलवायु शुष्क है, इसलिए अगर वहां की पारिस्थितिकी को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई में लंबा समय लग सकता है। भौगोलिक रूप से तिब्बत दुनिया की छत है, इसलिए प्राकृतिक रूप से यह ठंडा स्थान है और वहां काफी बर्फ रहती है। इसलिए यह एशिया की कई बड़ी नदियों का स्रोत भी है और 1 अरब से ज्यादा लोग इसकी नदियों पर निर्भर हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तिब्बती पठार पर असर उतना ही होता है जितना की दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर। मैंने सुना है कि चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी के कार्यकाल में तिब्बत के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से स्थानीय स्तर पर इन निर्देशों को लागू नहीं किया गया।

2. तिब्बती संस्कृतिः जबसे बौद्ध धर्म की नालंदा परंपरा तिब्बत पहुंची है, तिब्बत में ज्ञान के विभिन्न पहलुओं का विकास हुआ है। विशिष्ट नालंदा परंपरा में हृदय के अधिकतम बदलाव पर जोर दिया जाता है, न कि सिर्फ प्रार्थना और अनुष्ठानों पर। बुद्ध ने कहा है कि प्रयोग करें और अनुसंधान करें। तिब्बती बौद्ध संस्कृति शांति और अहिंसा की संस्कृति है। तिब्बती संस्कृति के संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि यह शांति, प्रेम और करुणा की परंपरा है। लेकिन इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। तिब्बती संस्कृति के माध्यम से हम आंतरिक शांति और शांत दिमाग के द्वारा एक खुशहाल और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म बहुत परिष्कृत है। यह सिर्फ प्रार्थना और अनुष्ठान नहीं है। बिना मतलब जाने अनुष्ठानों का पालन करना समय की बर्बादी है।

भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है और चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एकाधिकारवादी देश। भारत और चीन का रिश्ता वास्तविक शांति, पारस्परिक भरोसे और सहयोग पर आधारित होना चाहिए। दोनों देशों को इससे भारी फायदा होगा। सीमा पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती से अपने आप डर और संदेह का वातावरण पैदा होता है। दुनिया में हवा खुलापन और ज्यादा आज़ादी, ज्यादा लोकतंत्र और कानून के शासन की हवा बह रही है। इसलिए चीन सरकार कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह इस हवा से बच नहीं सकती और उसे इस रुख को अपनाना ही पड़ेगा। चीन के नए नेतृत्व को इस सच्चाई को समझना होगा। जैसा कि डेंग जियोपिंग ने कहा था, तथ्यों से सच्चाई की तलाश करें, तो तथ्य इस तरह से हैं। उन्हें सच्चाई पर आधारित नीति बनानी होगी। अयार्थवादी नीति से समस्या नहीं सुलझेगी।

तिब्बत की मौजूदा स्थितिः मैं तिब्बत के मसले के राजनीतिक पहलू पर कुछ नहीं कहूंगा। मै रिटायर हो चुका हूं और इस बारे में तिब्बत का चुना हुआ नेतृत्व जो कुछ भी कहेगा वही पूरी तरह से सच होगा। तिब्बत में स्थिति काफी गंभीर है। वहां एक समस्या है और समस्या न तो तिब्बतियों के लिए अच्छी है और न ही चीनियों के लिए। ताकत के इस्तेमाल से कभी भी समस्या का संतोषजनक हल नहीं निकाला जा सकता। तिब्बती सभ्यता काफी परिष्कृत है। कुछ चीनियों का कहना है कि तिब्बती काफी पिछड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीनी पुरातत्वविद ने एक बार मुझसे कहा था कि तिब्बती सभ्यता की अपनी जड़ है। अब तिब्बत के भीतर रहने वाले युवा पीढ़ी की भावना और एकता मेरी पीढ़ी से भी ज्यादा मजबूत है।

चीन के उभार की तिब्बत में होगी परीक्षा

(वाल स्ट्रीट जर्नल, 14 नवंबर) डॉ. लोबसांग सांगे

अपने एशिया दौरे के दौरान राष्ट्रपति ओबामा को मानवाधिकार उल्लंघनों पर रोशनी डालनी चाहिए

अमेरिकी राष्ट्रपति बराम ओबामा का अपने दोबारा चुने जाने के बाद पहली विदेश यात्रा में एशिया का दौरा करने का निर्णय इस बात को फिर से पुष्ट करता है कि उनके प्रशासन की विदेश नीति में एशिया केंद्रबिंदु पर है। उनका यह दौरा समूचे एशिया में आकर्षण का केंद्र रहेगा, खासकर तिब्बत में। इस दौरान ओबामा कम्बोडिया और थाइलैंड जैसे प्रमुख बौद्ध देशों की यात्रा करेंगे और वह बर्मा का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो कि एक बौद्ध बहुसंख्या वाला देश है। उनका बर्मा जाना खासकर तिब्बतियों के लिए काफी अर्थपूर्ण बात है क्योंकि उस देश के स्वतंत्रता संग्राम में लगे लोगों की चीन से व्यापक स्वायत्तता हासिल करने के तिब्बत के प्रयास पर गहरी नजर थी। ओबामा की उपस्थिति से बर्मा की आज़ादी समर्थक नेता आंग सान सू द्वारा प्रतिबिंबित लोकतंत्र एवं आज़ादी की ताकतों के समर्थन के बारे में एक मजबूत संकेत मिलेगा। राष्ट्रपति थीन सीन के साथ मिलकर सू की अति नाजुक परिस्थितियों में काम कर रही हैं, क्योंकि सैन्य सरकार के घात लगाने का डर बना हुआ है।

बर्मा के लोग और उनकी नेता सुश्री सू की को बहुत कुछ सहना पड़ा है। 8,888 जनक्रांतियों को बुरी तरह कुचला गया है और सैन्य सरकार ने हजारों बर्मी लोकतंत्र आंदोलनकारियों की हत्या की है। सुश्री सू की 1990 के आम चुनावों में भारी बहुमत से जीतने के बावजूद करीब 15 साल तक नजरबंद रखी गईं। आधुनिक बर्मा के जनक उनके पिता आंग सान की 1947 में हत्या कर दी गई थी।

सुश्री सू की के संघर्ष और अनुभव उनकी तरह ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दलाई लामा से काफी मिलते–जुलते हैं। अपनी जनता से जबरन दूर कर दिए जाने के बावजूद दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थी समुदाय के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की है, धर्म और राजनीति को अलग किया है और अपनी राजनीतिक सत्ता को चुने हुए नेता सीक्योंग को सौंपा है। एक कार्यरत लोकतंत्र का यह मॉडल शरणार्थी समुदायों के बीच अनूठा है।

ओबामा को अपने इस दौरे का इस्तेमाल बौद्ध धर्म और लोकतंत्र के बीच संगतता के बारे में व्यापक तौर पर ध्यान दिलाने के लिए करना चाहिए। बर्मी और थाई जनता की तरह ही निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों ने भी लोकतंत्र निर्माण के लिए काम किया है। वास्तव में, बर्मा में केसरिया क्रांति के उभार के तरह ही तिब्बती भिक्षु भी पिछले 60 साल में तिब्बत में आज़ादी के लिए चल रहे अहिंसक संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर रहे हैं।

ओबामा प्रशासन को तिब्बत के मसले को 18वीं पार्टी कांग्रेस के दौरान चुने गए नए चीनी नेतृत्व के समक्ष ज्यादा गंभीरता से रखना चाहिए। तिब्बत में तिब्बती न्याय के लिए चीख रहे हैं, खासकर पूजा करने की आज़ादी के लिए जिसका पिछले सालों में चीन ने वादा किया था। अब तक करीब 72 तिब्बती खुद को आग लगा चुके हैं, मार्च 2011 के बाद ही ऐसी 70 घटनाएं और इसी महीने सिर्फ एक दिन में ऐसी पांच घटनाएं हो चुकी हैं। सभी आत्मदाह करने वालों का सामूहिक विलाप यह रहा है कि परमपावन दलाई लामा को तिब्बत वापस लाया जाए और तिब्बतियों को आज़ादी दी जाए।

तिब्बतियों ने पिछले पांच दशक में लोकतंत्र और अहिंसा में भरोसा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का फिर से आश्वस्त करने वाला बयान आया है कि अमेरिका मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है और राजदूत गैरी लॉक ने हाल में तिब्बती इलाकों का दौरा किया है। ओबामा प्रशासन के लिए अगले चार साल तीन बौद्ध एशियाई देशों की सकारात्मक शुरुआत के साथ और आगे बढ़ने के होंगे और वह चीन के समक्ष तिब्बत का मसला उठाकर एशिया को धुरी बनाने की अपनी योजना को और सार्थक बना सकते हैं।

तिब्बत के मसले को हल करने में मदद करना न केवल अमेरिकी मूल्यों के अनुरूप है, बल्कि यह एक सामरिक अनिवार्यता भी है। चीन के एक आर्थिक दिग्गज से संभावित महाशक्ति बनने के उभार में अमेरिका और शेष दुनिया का काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चीन में असल स्थिरता लाने और एशिया में शांति कायम करने के लिए चीन की असली परीक्षा इस बात से होगी कि वह चीनी संविधान के ढांचे के भीतर तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने को किस हद तक इच्छुक है। तिब्बत की समस्या को हल करने से चीन और भारत के बीच संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी। इससे तिब्बती फिर से तिब्बत के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधक की अपनी परंपरागत भूमिका में आ जाएंगे, जिसमें तिब्बत से निकलने वाली एशिया की कई महान नदियों का प्रबंधन भी शामिल होगा जिन पर करोड़ों एशियाइयों की जीविका और उनका अस्तित्व निर्भर है।

तिब्बत के मसले पर अमेरिका के चीन के साथ सफल संपर्क का करोड़ों भारतीय, नेपाली, भूटानी और मंगोलियाई नागरिक स्वागत करेंगे जो कि कभी तिब्बत को अपनी संस्कृति के स्रोत और अपने धार्मिक विश्वास की मातृभूमि के रूप में देखते थे। आज चीन में 30 करोड़ से ज्यादा बौद्ध हैं और ऐसे करोड़ों बौद्ध एशिया के अन्य देशों में भी रहते हैं। तिब्बत की स्वायत्तता के मसले पर चीन साध सकने की अमेरिका की क्षमता चीन के बेहतरीन लोगों सोच के अनुरूप भी होगी। जब तिब्बत में 2008 में शांतिपूर्ण और सतत विरोध प्रदर्शनों की लहर चल पड़ी थी तो कई चीनी बुद्धिजीवी, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं (जिनमें जेल में बंद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विद्वान लिउ शियाओबो भी थे) ने चीन सरकार को एक खुला पत्र लिखकर प्रशासन से यह अनुरोध किया था कि वह इस मसले के संवाद के रास्ते से हल के लिए एकतरफा दुष्प्रचार बंद करें।

मुझे लगता है कि यह अब चीन में बहुत से लोगों की भावना है और तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों की भी यही आकांक्षा है। इस साझे भावना पर राष्ट्रपति ओबामा का नेतृत्व अमेरिका के एशिया को धुरी बनाने की सोच को अत्यंत जरूरी मानवाधिकार पहलू से जोड़ सकता है।

श्री सांगे सिक्योंग (तिब्बती जनता के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता) और दलाई लामा के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं।

चीन में सत्ता परिर्वतन और तिब्बत का सवालः डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

1949 में चीन में हुये गृह युद्ध के फलस्वरुप वहां की सत्ता पर माओ के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी पार्टी का कब्जा हो गया था । माओ जब तक जिन्दा रहे तब तक तो सत्ता उन्हीं के पास रही लेकिन उनकी मौत के दस साल बाद सत्ता परिवर्तन की परम्परा स्थापित हुई । उसी के अनुसार पार्टी की अठाहरवीं कांग्रेस में नये नेतृत्व के पास सत्ता सूत्र चले गये ।

राष्ट्रपति हू जिनताओ के स्थान पर शी जिंगपिंग और प्रधानमंत्री वेन जिआवाओ के स्थान पर ली किछीयांग ने पद संभाल लिया है । इस परिवर्तन का विश्व के लिये क्या अर्थ है , इस पर लम्बे अरसे तक बहस चलती रहेगी । लेकिन महत्वर्पूण प्रश्न है कि इस परिवर्तन का भारत और तिब्बत के लिये क्या अर्थ है ? दरअसल तिब्बत पर भी असली संकट चीन के गृह युद्ध में माओ को मिली सफलता के बाद ही शुरु हुआ । 1949 में ही चीन ने तिब्बत पर शिकंजा करना शुरु कर दिया था और 1959 तक तिब्बत पूरी तरह चीन के कब्जे में आ चुका था । भारत पर चीन की छाया भी उसके तिब्बत कब्जे के बाद ही पड़नी शुरु हुई , जबकि भारत ने चीन के तिब्बत कब्जे का विरोध भी नहीं किया था । न तो अब चीन में वह पीढ़ी या नेतृत्व रहा है , जिसने गृह युद्ध में भाग लिया है और न ही तिब्बत में वह पीढ़ी बची है जिसने 1959 के महा जन विद्रोह को देखा था या फिर दलाई लामा का पलायन देखा था । इस मामले में भारत को ही अपवाद कहा जा सकता है कि वह आज साठ साल बाद भी चीन को लेकर नेहरु की नीति का ही अनुसरण कर रहा है ।

तिब्बत की जवान हो चुकी नई पीढ़ी में छटपटाहट ज्यादा बढ़ने लगी है । चीन के खिलाफ उनका गुस्सा ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई में तेज़ी भी आ रही है । फिलहाल तिब्बती युवाओं का आजादी आन्दोलन अहिंसक ही है । यह दलाई लामा का प्रभाव ही कहा जा सकता है । लेकिन यह कब तक बना रहेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । तिब्बत में उभर रहे असन्तोश का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल में 70 से भी ज्यादा लोगों ने चीनी आधिपत्य के विरोध में आत्मदाह कर लिया है ।

आत्मदाह करने वालों में ज्यादा लोग युवा वर्ग में ही आते हैं । यह वह पीढ़ी है जिसने दलाई लामा को देखा नहीं है केवल उनका नाम सुना है। तब भी वे उनके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं । आजादी के इस आन्दोलन की ज्वाला बुद्ध मंदिरों व मठों के भिक्षु भिक्षुणियां ही जला रहे हैं, जबकि चीन सरकार पिछले साठ साल से इन मठों की पहचान को समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है । आजादी के इस आन्दोलन का अर्थ है कि चीन सरकार अपने अभियान में सफल नहीं हुई । जब से चीनी साम्यवादी पार्टी की 18वीं कांग्रेस शुरू हुई उसी के कुछ दिनों के बीच आठ तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं ।

लेकिन असली प्रश्न है कि चीन के नये नेता क्या तिब्बत के प्रति अपनी नीति बदलेंगे या फिर उसी पुरानी नीति को ही जारी रखेंगे ? एक बार ऐसी आशा माओ के मरने के बाद देंग शिओफेंग के काल में बंधी थी, जब उसने कहा था कि आजादी से कम और किसी भी विकल्प पर तिब्बत को लेकर बात हो सकती है देंग ने ही दलाई लामा के प्रतिनिधियों को तिब्बत में बुलाया था । शायद देंग को आशा थी कि अब तक दलाई लामा का प्रभाव तिब्बत के लोगों पर कम हो गया होगा । लेकिन जब उसका यह विचार ग़लत निकला तो वह तिब्बत को लेकर अपने इस प्रयोग से भी पीछे हट गये । शी जिंगपिंग के एजेंडा में तिब्बत को लेकर ऐसी कोई कल्पना है इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है ।

भारत के प्रति चीन की नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आयेगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये । भारत को लेकर चीन की नीति उसके तात्कालिक हितों पर नहीं बल्कि दूरगामी रणनीति पर आधारित है । चीन नहीं चाहता की विश्व राजनीति में भारत का महत्वर्पूण स्थान बने । वह उसे उसके पड़ोसी देशों में ही उलझाये रखना चाहता है । इसीलिये चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई करता रहता है । चीन का नया नेतृत्व भारत के प्रति अपनी पुरानी बदलेगा , इसका कोई ठोस कारण दिखाई नहीं देता । विदेश नीति में मौलिक परिर्वतन की संभावना हो सकती है यदि देश में सरकार परिर्वतन किसी वैचारिक आधार पर हुआ हो या फिर नया नेतृत्व पुराने नेतृत्व से किसी बड़े संघर्ष के बाद निकला हो । फिलहाल चीन में ऐसी स्थिति नहीं है ।

नया नेतृत्व हू जिनताओ की पसन्द ही कही जा सकती है । इस लिये भारत के प्रति चीन की नीति पूर्ववत ही रहेगी , यही मान कर चलना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य से भारत की विदेश नीति का निर्णय करने वालें में अभी भी बहुमत ऐसे लोगों का ही है जो माओ नेहरू से हाथ मिलाने के लिये पहले आगे बढ़े, के आधार पर नीति निर्धारित करते हैं । एक पूर्व विदेश सचिव अभी भी देश को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चीन से भारत के रिश्ते इसलिये खराब हुये क्योंकि दिल्ली ने 1959 में दलाई लामा को शरण दे दी थी । वे अभी भी तुष्टीकरण से ही चीन को प्रसन्न करने में ही विश्वास रखते हैं । इसी प्रकार के नीति निर्धारक शी जिंगपिंग के सत्ता आरोहण में ज़रुरतों से ज्यादा अर्थ तलाशने की कोशिश कर रहे हैं ।

यह ताज्जुब की बात है कि तिब्बती स्वतंन्त्रता संग्राम में एक साल में 70 से भी ज्यादा आत्मदाह होने पर भी भारत सरकार के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला । सरकार चीन के साथ मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा तो उठा ही सकती है। कूटनीति के स्तर पर यदि भारत सरकार चीन से उसी की भाषा में बात नहीं करेगी तो यक़ीनन चीन का नया नेतृत्व कुछ कर दिखाने के लालच में भारत के प्रति और भी आक्रामक हो सकता है । वैसे भी अब चीन ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि 1962 में भारत पर आक्रमण का कारण माओ की चीन की राजनीति पर कमज़ोर होती पकड़ ही थी । अब भी यदि चीन में आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो देश का ध्यान बंटाने के लिये भारत निशाना नहीं बनेगा, इसकी क्या गारंटी है ? भारत सरकार को अपनी चीन नीति इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिये, न कि चीन की अठाहरवीं कांग्रेस में दिये गये भाषणों को ध्यान में रखकर । तिब्बत चीन को नियंत्रण में रखने का एक कारगर माध्यम है न कि भारत चीन संबंध में अवरोधक , इस तथ्य को जितना जल्द ह्रदयंगम कर लिया जाये उतना ही कल्याणकारी होगा ।